आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 19.08.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- भराड़ीसैंण में विधानसभा के मॉनसूत्र सत्र के पहले दिन सदन में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा।
- उत्तराखण्ड में जल संरक्षण की ऐतिहासिक पहल। भराड़ीसैंण में "डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना" का शुभारंभ।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य–योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही स्वयं सहायता समूह की सराहना की। सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया।

विधानसभा मॉनसून सत्र

चमोली जिले के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में आज से मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। नियम 310 के तहत कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वहीं कांग्रेस सदस्यों ने नैनीताल में हुए बवाल पर भी शोर शराबा किया। इस दौरान कांग्रेस सदस्य शोर–शराबा करते हुए वेल तक पंहुच गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कछ समय तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा के कुकृत्यों ने प्रदेश की छवि खराब की है।

वहीं, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विपक्ष को सिर्फ हंगामा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

उधर, सत्र में अनुपूरक बजट के साथ ही सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक, लोक साक्ष्य विधेयक, धर्मांतरण कानून संशोधन विधेयक और लोकतंत्र सेनानी पेंशन विधेयक शामिल हैं।

<u>योजना शुभारंभ</u>

उत्तराखण्ड में जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए आज एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने स्वामी राम विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट के सहयोग से "डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना" का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वाइब्रेंट बर्ड ऑफ कोटद्वार के नाम से फोटो संग्रह का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाकर राज्य के जल संकट को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने कहा कि जल संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की भविष्य की जीवनरेखा है। उन्होंने कहा कि "भूजल पुनर्भरण भविष्य की जल सुरक्षा का आधार बनेगा। यह योजना उत्तराखण्ड में सतत जल प्रबंधन और जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।"

कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गत आठ जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भराड़ीसैंण और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के बीच एक एम.ओ.यू हुआ था। डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना के अंतर्गत उपचारित वर्षा जल को निष्क्रिय हैंडपंपों में इंजेक्ट कर भूजल स्तर को बढ़ाया जाएगा। इस तकनीक को स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। योजना के पहले चरण में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और चौखुटिया विकासखंडों के 20 चयनित हैंडपंपों

को पुनर्भरण कर पुनः क्रियाशील बनाया जाएगा। यह प्रयास उत्तराखण्ड में जल प्रबंधन के लिए एक स्थायी समाधान की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम ने योजना की तकनीकी प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यह तकनीक किस प्रकार वर्षा जल को फिल्टर और ट्रीट कर सीधे भूजल भंडार तक पहुंचाती है, जिससे सूखे हैंडपंप फिर से जीवंत हो जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई, जिसमें गैरसैंण क्षेत्र के गांवों में लागू की गई तकनीक और उसके परिणामों को दिखाया गया।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य–योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसके तहत जीवन में आसानी, कारोबार सुगमता और समावेशी समृद्धि के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री को शासन में सरलता, आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने और इन उपायों से नागरिकों के लिए सीधा लाभ सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के बाद यह उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई। स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों और करों का बोझ कम करने के रूप में दीवाली उपहार का वायदा किया था।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सुधारों का उद्देश्य जीवन में आसानी लाना, कारोबार सुगमता और समृद्धि को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री फीडबैक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आज सुबह भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यो की सराहना की और सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने उत्तराखण्ड आने वाले पर्यटकों से अपील की, कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर अपनी यात्रा व्यय का पांच प्रतिशत स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विधानसभा परिसर में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात कर उनके खाने–पीने और रहने की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री धामी ने कहा कि ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने में लगी बहनों का समर्पण और स्वच्छ व स्वस्थ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे सफाई कर्मियों की लगन 'विकसित उत्तराखंड' की दिशा में सामूहिक प्रयास का अनुपम उदाहरण है।

उपराष्ट्रपति नामांकन

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन– एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्री राधाकृष्णन ने कल शाम नई दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल के नेताओं के साथ एक शिष्टाचार बैठक की। बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी एनडीए नेता नामांकन दाखिल करने के समय उपस्थित रहेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होगी। इसमें सभी नेताओं का श्री सीपी राधाकृष्णन से औपचारिक परिचय कराया जाएगा।

चीनी मिल

हरिद्वार जिले में भगवानपुर तहसील प्रशासन ने इकबालपुर चीनी मिल पर 9 करोड़ बकाया होने पर 77 बीघा भूमि कुर्क की है। उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। मिल पर विशेष निधि ऋण, राज्य कर और अन्य मदों में लगभग 9 करोड़ रुपये बकाया है। प्रशासन ने वसूली प्रक्रिया को तेज़ करते हुए मिल के नाम दर्ज भूमि में लगभग 77 बीघा को कुर्क किया है। उप जिलाधिकारी के अनुसार चीनी मिल पर लंबे समय से बकाया राशि की वसूली लंबित थी, जिसे लेकर किसानों और प्रशासन दोनों की ओर से दबाव बढ़ता जा रहा था।

शोधार्थी तिथि

उत्तराखंड राज्य संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसरों और संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेशित प्री–पीएचडी कोर्स वर्क – शैक्षणिक सत्र 2024–25 कर रहे शोधार्थियों के लिए लघुशोध जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ की ओर से जारी सूचना के अनुसार शोधार्थी अपना लघुशोध अपने शोध निर्देशक से अग्रसारित कर निर्धारित अवधि में जमा कर सकेंगे।